

A-4
1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

संख्या : 77 / 2021

अमित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी ग्राम बडबर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

--- अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।

--- रेस्पोजेन्ट

अन्तर्गत धारा 22(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955, अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.2021 जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।

उपस्थित:-

1. श्री संदीप कुमार पूनियां, अभिभाषक- अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती कमल कुमार मीणा, विभागीय पैरोकार- रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.07.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट (उचित मूल्य दुकानदार) का अधिकार पत्र 237/2018 एवं पोस कोड संख्या 30833 को निरस्त कर दिया गया है। अपीलान्ट निर्दोष व्यक्ति है जिसको झूठा फंसाया जाकर अभियोजित किया जा रहा है। अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता अंकित कुमार ने अपीलान्ट के विरुद्ध झूठी शिकायत की है क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दूसरे लोगो के बहकावे में आकर शिकायत की गई है और न ही कोई सद्भावी व्यक्ति है। वह तो स्वयं अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायत झूठे व कल्पित तथ्यो पर प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 आलौच्याधीन आदेश है। चूंकि जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच किये जाने का कोई आधार नहीं था। वह तो मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत पर शिकायतकर्ता के साथ प्रकरण बनाकर अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से ही जांच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा करवाई गई है जबकि मौके पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नहीं थी। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट का कृत्य अवैध है और उक्त आदेश आलौच्याधीन आदेश है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अधिकार पत्र का निलम्बन (अमित कुमार पोस कोड सं. 30833) गलत है। इस प्रकार जब निलम्बन ही निष्प्रभावी है तो लाईसेंस का निरस्तीकरण किया जाना स्वतः ही अवैध हो गया, नियम विरुद्ध हो गया। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट का आदेश गलत आदेश है। अपीलान्ट के विरुद्ध जो साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये हैं वे सभी कुटरचित व झूठे हैं। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्ता का प्रमाणीकरण नहीं है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही दूषित कार्यवाही है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट किया है। दिनांक 28.06.2021 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर गये जो कि खुली पाई गई और अपीलान्ट वही मिला एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार सही पाया गया। मौके पर

अमित कुमार झुंझुनू

शिकायतकर्ता अंकित कुमार भी उपस्थित आये शिकायत की जांच करवाई जिसमें पोस मशीन के अनुसार
 स्टॉक का भौतिक सत्यापन सही पाया गया। उक्त शिकायत कर्ता द्वारा रंजिसवंश शिकायत की गई।
 दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निलम्बन कर दिया गया एवं दिनांक 30.06.2021 को ही
 प्रार्थी को कारण बताओं नोटिस दिया गया। अतः प्रार्थी को कोई भी सुनवाई का मौका दिये बिना ही प्रार्थी
 का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है जो कि अवैध एवं मनमाना है व नियम विरुद्ध है एवं
 प्रार्थी/अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 30.06.2021 निलम्बन का पारित कर
 दिया गया जो कि अपने आप में रेस्पोजेन्ट का कृत्य मनमाना एवं दंभी कृत्य स्पष्ट होता है एवं उक्त
 निलम्बन आदेश को उचित ठहराने के लिए रेस्पोजेन्ट ने आदेश दिनांक 28.07.2021 से प्रार्थी का प्राधिकार
 पत्र संख्या 237/2018 एवं पोस कोर्ड संख्या 30833 को निरस्त कर दिया गया जो कि मनमाना, अवैध एवं
 प्रकृतिक न्याय के विरुद्ध है। दिनांक 29.06.2021 को मौके पर जांच की गई उक्त जांच भी प्रार्थी द्वारा
 प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के बिना ही जांच की गई एवं उक्त साक्ष्यों के बिना रिकार्ड पर लिए जांच की गई
 है एवं प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये हुए की गई है जो कि अनुचित एवं अवैध है। उक्त रेस्पोजेन्ट
 द्वारा केवल कांत्पनिक रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाकर एक ही दिन में जांच कर दिनांक
 30.06.2021 को अपीलान्त का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया जो कि गलत व निरस्त होने योग्य है। जो
 कांत्पनिक रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि रिपोर्टकर्ता की साजिस से मिलकर तैयार की गई है। अपीलान्त
 द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनको बिना कनसिडर किये हुए उक्त जांच रिपोर्ट तैयार की गई है।
 उक्त रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन सही पाया गया एवं प्रार्थी को 2018 में राशन डीलर नियुक्त किया गया।
 पूर्व से चले आ रहे राशन कार्ड पर ही प्रार्थी अपीलान्त द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं
 राशन कार्ड बनाने का कार्य विकास अधिकारी पंचायत समिति का होता है। प्रार्थी द्वारा ना कोई यूनिट
 राशन कार्ड में बढ़ाई गई क्योंकि उक्त कार्य सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी का होता
 है। प्रार्थी द्वारा उक्त यूनिट के अनुसार ही राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं रेस्पोजेन्ट द्वारा बिना
 किसी सुने व पढे ही अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का मन बना लिया और दिनांक 28.07.2021 को
 अपीलान्त को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि विधि विरुद्ध आदेश है उक्त रेस्पोजेन्ट का आदेश
 गलत व आधारहीन होने से न्याय संगत नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवाद,
 परिव्रादी श्री अंकित कुमार द्वारा की गई शिकायत की जांच दो राशन डीलर सुनिल कुमार एवं अंकित
 कुमार की एक ही जांच की गई है जो कि अवैध व मनमाना है। प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक
 30.06.2021 का जबाब भी प्रार्थी/अपीलान्त द्वारा दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। फिर भी
 रेस्पोजेन्ट द्वारा दिनांक 28.07.2021 को निरस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया जो कि अनुचित एवं
 अवैध है। प्रार्थी/अपीलान्त द्वारा पूर्व के कारण बताओ नोटिस का जबाब दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत
 किया गया उसके उपरान्त प्रार्थी/अपीलान्त को दिनांक 22.07.2021 को एक अन्य संशोधित कारण बताओ
 नोटिस दिया जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.07.2021 को निरस्त कर दिया गया जो कि प्रार्थी
 को बिना सुनवाई का मौका दिये (अन फेयर ट्रेड प्रेटिक्स की श्रेणी में आता है।) प्रार्थी अपीलान्त का
 आलौच्याधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, उक्त
 प्रकरण के समान प्रकृति के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा अपील सं. 61/2021 उनवान कंवर सिंह
 बनाम जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को दिनांक 13.09.2021 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी अपीलान्त
 का आदेश समान प्रकृति का होने के कारण उक्त आलौच्या आदेश दिनांक 28.07.2021 भी निरस्तनीय है।
 उक्त अपील अपीलान्त अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर
 जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्त का लाईसेन्स
 नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की
 पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्त निर्दोष व्यक्ति है जिसको झूठा फंसाया जाकर अभियोजित
 किया जा रहा है। अपीलान्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता अंकित कुमार ने अपीलान्त के विरुद्ध
 झूठी शिकायत की है क्योंकि वह अपीलान्त से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दूसरे लोगो

इस बहकावे में आकर शिकायत की गई है और न ही कोई सद्भावी व्यक्ति है। वह तो स्वयं अपीलान्ट से उचित रखता है। इस प्रकार शिकायत झूठे व काल्पनिक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन है। जांच पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नहीं थी। इस प्रकार जब निलम्बन ही निष्प्रभावी है तो लाईसेंस का निरस्तीकरण किया जाना स्वतः ही अवैध हो गया, नियम विरुद्ध हो गया। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट का आदेश मनमाना आदेश है। अपीलान्ट के विरुद्ध जो साक्ष्य व प्रमाण उपलब्ध करवाये गये हैं वे सभी कुटरचित व बनावटी हैं। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्ता का प्रमाणीकरण नहीं है। दिनांक 29.06.2021 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दूकान पर गये जो कि खुली पाई गई और अपीलान्ट वही मिला एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार सही पाया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 30.06.2021 निलम्बन विरुद्ध प्रेषित कर दिया गया जो कि अपने आप में रेस्पोजेन्ट का कृत्य मनमाना एवं दंभी कृत्य स्पष्ट होता है। दिनांक 29.06.2021 को मौके पर जांच की गई उक्त जांच भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के बिना ही जांच की गई एवं उक्त साक्ष्यों के बिना रिकार्ड पर लिए जांच की गई है एवं प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये हुए की गई है जो कि अनुचित एवं अवैध है। जांच रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन सही पाया गया एवं प्रार्थी को 2018 में राशन डीलर नियुक्त किया गया। पूर्व से चले आ रहे राशन कार्ड पर ही प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का वितरण किया गया एवं राशन कार्ड बनाने का कार्य विकास अधिकारी सहायक समिति का होता है। प्रार्थी द्वारा ना कोई यूनिट राशन कार्ड में बढ़ाई गई क्योंकि उक्त कार्य सचिव, ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी का होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त यूनिट के अनुसार ही राशन सामग्री का वितरण किया गया है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पूर्व के कारण बताओ नोटिस का जबाब दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त प्रार्थी/अपीलान्ट को दिनांक 22.07.2021 को एक अन्य संशोधित कारण बताओ नोटिस दिया जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.07.2021 को निरस्त कर दिया गया जो कि प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये (अन फेयर ट्रेड प्रेटिक्स की श्रेणी में आता है) प्रार्थी अपीलान्ट का आलौच्याधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, उक्त प्रकरण के समान प्रकृति के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा अपील सं. 28/2021 उनवान कंवर सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को दिनांक 13.09.2021 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी अपीलान्ट का आदेश समान प्रकृति का होने के कारण उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.07.2021 भी निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच में अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री के गबन व दुरुपयोग की गंभीर अनियमितता पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा फर्जी यूनिट बढ़ाने/घटाने, एक से अधिक राशनकार्ड बनाने, फर्जी आधार सीडिंग करवाने में अपीलान्ट की अहम भूमिका रही है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2021 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 237/18 निरस्त किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार से हैं :-

1. अपीलान्ट तथा सुनिल कुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बड़बर द्वारा उनको आवंटित स्थान से अलग दुसरे अनाधिकृत स्थान पर राशन वितरण का कार्य किया जा रहा था, जो उनको आवंटित प्राधिकार पत्र के विपरित है। अपीलान्ट द्वारा नियमों के विरुद्ध एक अनाधिकृत स्थान पर राशन वितरण कार्य किया है।
2. अपीलान्ट द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के आधार की राशन कार्ड से साथ फर्जी सिडिंग करवाकर राशन का गबन किया गया है, जो रिपोर्ट दिनांक 05.07.2021 से साफ है।

अधीनस्थ

